प्रकाश वीडब्ल्यूआर-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2010 का सीआरआर नंबर 3228

17 अगस्त 2012

भारतीय दंड संहिता, 1860 - एस.एस. 148, 149, 323, 324, 285, 336 और 30 7/42 7 - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - एसएस, 173(8) और 3 21 - उस आदेश को चुनौती जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन पक्ष के आवेदन को वापस लिया जाए घोषित अपराधी बताए गए कुछ उत्तरदाताओं के खिलाफ लंबित अभियोजन की अनुमति दी गई - याचिका की अनुमति - अभियोजन वापस लेने के कारणों पर चर्चा की गई

यदि पुराना है, तो सीआरपीसी की धारा 321 के तहत, सरकारी अभियोजक को अदालत की सहमति के अधीन अभियोजन से हटने की सामान्य कार्यकारी शक्ति प्राप्त है। यह तभी किया जा सकता है जब अभियोजक मामले से हटने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र कदम उठाए और इसके लिए कारण भी बताए।

(पैरा 7)

आगे कहा गया कि अभियोजन से हटने की शक्ति हमेशा एक अपवाद है, इसका प्रयोग न्याय प्रशासन के हित में किया जाना चाहिए। वापसी के कारणों से अदालत की न्यायिक चेतना को संतुष्ट होना चाहिए और केवल वैध आधार के बिना वापसी का निर्देश देने वाला सरकार का आदेश सरकारी अभियोजक द्वारा आवेदन दायर करने के लिए पर्याप्त नहीं है और अदालत द्वारा वापसी का आदेश पारित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

(पैरा 10)

इसके अलावा, यह माना गया कि आपराधिक मामले से वापसी के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, आपराधिक मामलों से वापसी के लिए सरकारी अभियोजक का कार्य एक सार्वजनिक उद्देश्य से संबंधित है। सरकारी वकील अदालत का एक अधिकारी होता है और उसका कर्तव्य सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करना है। ऐसा करने के लिए उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह केवल न्याय प्रशासन के हित में है। निष्पक्षता, दक्षता और जवाबदेही अभियोजन प्रणाली की महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं। इन उद्देश्यों को सरकारी अभियोजक द्वारा शक्ति के स्वतंत्र प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी वकील को आपराधिक मामलों में अन्य अनुचित प्रभावों से मुक्त होकर आगे बढ़ना आवश्यक है। विवादित आदेश केवल सुन्नियों और अनुमानों पर आधारित है। ट्रायल कोर्ट का आक्षेपित आदेश उन ठोस कारणों और परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट रूप से मौन है, जिन पर वापसी की अनुमति दी गई है। अभियोजन मामले से हटने के कारणों और परिस्थितियों को अदालत की न्यायिक अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए, जिनका विवादित आदेश में अभाव है।

(पैरा 12)

आगे कहा गया, कि यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सहमति देने से पहले, यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि न्याय के हित के अलावा, किसी बाहरी आधार पर वापसी की मांग नहीं की जा रही है। अदालत को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य के खिलाफ अपराध का फैसला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि सरकार ने अभियोजन से हटने का निर्देश दिया है, सहमति नहीं दी जानी चाहिए।

(पैरा 13)

आगे कहा गया है कि, ब्लैकस्टोन लिखते हैं, "न्याय राजा से उसके मुफ्त उपहार के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि वह जनता का प्रबंधक होता है कि जिसे यह देना है उसे दे दे।" इस मामले में सरकारी वकील द्वारा अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने कार्यालय के उच्चतम नैतिक और पेशेवर मानक को ध्यान में रखते हुए आवेदन दायर नहीं किया गया है। सरकारी

वकील का अदालत, जनता, पीड़ितों, अभियुक्तों और गवाहों के प्रति अलग-अलग स्तर का दायित्व होता है। मुकदमा न चलाने का गलत निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है।

(पैरा 14-15)

याचिका मंजूर.

याचिकाकर्ता के वकील विजय कुमार जिंदल।

सिद्धार्थ सरूप, उप महाधिवक्ता, हरियाणा।

अशोक कुमार, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

मनिंदर कौर, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के लिए वकील।

अरविंद सिंह, प्रतिवादी संख्या 8 और 9 के वकील।

पी अरमजीत सिंह, जे.

(1) वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में चुनौती दिनांक 25.8.2010 के आदेश को है जिसके तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक कोर्ट), कमल ने उत्तरदाताओं संख्या 2 से 9, और दो के खिलाफ लंबित अभियोजन से हटने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी है। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत एक आवेदन पर अन्य आरोपी, अर्थात् गोल्डी और कुक्की, जिन्हें घोषित अपराधी बताया गया है। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा स्थानांतरित किया गया।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि धारा 148, 149,323, 324,285, 336,307/427आईपीसी के तहत एफआईआर नंबर 344 दिनांक 23.6.2005 को प्रतिवादी नंबर 2 से 9 और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सिटी कमल में दर्ज किया गया था। इस आधार पर कि उन्होंने एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा का गठन किया, दंगा करने का अपराध किया और प्रकाश वीर और राजेंद्र को चोट पहुंचाई। चाय लान प्रस्तुत की गई जिसमें उपस्थित उत्तरदाताओं संख्या 2 से 9 को मुकदमे का सामना करने के

लिए भेजा गया और गोल्डी और कुक्की को घोषित अपराधी के रूप में दिखाया गया। विचारोपरांत दिनांक 26.9.2007 को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश कमल द्वारा आरोप गठित किया गया। इसके बाद, अभियोजन साक्ष्य के लिए सी'$ई तय की गई। जब मुकदमा चल रहा था, दो साल से अधिक समय के बाद, आवेदन दिनांक 13.7.2009, (अनुलग्नक पी-2) धारा 321 सीआरपीसी के तहत। विजय कुमार और संबंधित एफआईआर में अन्य आरोपियों के संबंध में अभियोजन से वापसी के लिए इस आधार पर आवेदन किया गया था कि आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट में हटा दिया गया है, लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी है पक्षकारों के बीच मामला लंबित है, वापसी से शांति, सौहार्द और भाईचारा कायम रहेगा, मामले की सफलता की कोई संभावना नहीं है, वर्तमान मामले में महिला सदस्य भी शामिल हैं, और लोक अभियोजक को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है कुछ दस्तावेज़ जिनमें यह उल्लेख है कि आरोपियों को राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण फंसाया गया है।

(3) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), कमल ने वापसी के लिए आवेदन पर विचार किया और दिनांक 16.1.2010 (अनुलग्नक पी -3) के आदेश के तहत कारण दर्ज करते हुए इसे खारिज कर दिया कि मामले से वापसी से शांति और सद्भाव नहीं मिलेगा। दोनों पक्षों के बीच और सरकारी वकील ने अप्रासंगिक बाहरी विचारों से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र एजेंट के रूप में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। उत्तरदाताओं संख्या 2 से 9 तक संपर्क किया गया

दिनांक 16.1.2010 के आदेश को रद्द करने के लिए यह न्यायालय। इस न्यायालय ने दिनांक 15 जुलाई 2010 के आदेश द्वारा दिनांक 16.1.2010 के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि मामले में अब पक्षों के बीच समझौता हो गया है और ट्रायल कोर्ट को ताजा परिस्थितियों के आलोक में धारा 321 के तहत आवेदन पर नए सिरे से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। जब यह आदेश याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया तो याचिकाकर्ता ने सीआरएल

का रुख किया। Mise. 2010 की संख्या 39595 में उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका में बताया गया कि पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं है। अंततः, दिनांक 17.8.2010 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश दिया: -

"...यह आदेश दिया जाता है कि 15 जुलाई 2010 के आदेश से यह पंक्ति "कि मामले में अब समझौता हो गया है" को हटा दिया जाए।"

(4) इसके बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), कमल की अदालत द्वारा दिनांक 25.8.2010 के आक्षेपित आदेश के तहत मामले पर नए सिरे से निर्णय लिया गया, जिसके तहत आरोपी के खिलाफ अभियोजन से वापसी के आवेदन की अनुमति दी गई है। इसलिए, तत्काल याचिका।

(5) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि आवेदन दिनांक 13.7.2009 (अनुलग्नक पी-2) वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के मेमो के अनुसार सरकार के कहने पर दायर किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कमल द्वारा अभियोजन से वापसी हेतु जारी क्रमांक 8/9/2009- 3JJ(1) दिनांक 15.6.2009. यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सरकारी वकील द्वारा दायर आवेदन बिना सोचे समझे दायर किया गया है, और यह श्री तेजिंदर पाल सिंह मान, पूर्व विधायक के राजनीतिक प्रभाव और सरकार के पत्र का परिणाम है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अभियोजन से हटने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और न ही इससे पार्टियों के बीच शांति और सद्भाव आएगा क्योंकि पार्टियों के बीच इस मामले पर कभी समझौता नहीं हुआ है। यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष गलत बयान भी दिए गए कि पार्टियों ने समझौता कर लिया है, जिसे बाद में याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में एक आवेदन दायर करके सही किया।

(7) सीआरपीसी की धारा 321 के तहत, सरकारी अभियोजक को अदालत की सहमति के अधीन अभियोजन से हटने की सामान्य कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। यह तभी किया जा सकता है जब अभियोजक मामले से हटने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र कदम उठाए और इसके लिए कारण भी बताए।

(8) अभियोजक को अभियोजन से हटने को उचित ठहराने वाले कारणों और परिस्थितियों के संबंध में अदालत को संतुष्ट करना होगा। धारा 321 सी.आर.पी.सी. इस प्रकार पढ़ता है:-

"321. अभियोजन से हटना किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, न्यायालय की सहमति से, निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से या तो आम तौर पर या किसी के संबंध में वापस ले सकते हैं। और भी अधिक अपराध जिनके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया है; और, ऐसी वापसी पर, -

(ए) यदि यह आरोप तय होने से पहले किया गया है, तो आरोपी को ऐसे अपराध या अपराध के पहलू से मुक्त कर दिया जाएगा;

(बी) यदि यह आरोप तय होने के बाद बनाया गया है, या जब इस संहिता के तहत किसी आरोप की आवश्यकता नहीं है, तो उसे ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में बरी कर दिया जाएगा;

बशर्ते कि जहां ऐसा अपराध हो

(i) किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ था जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, या

(ii) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) द्वारा जांच की गई थी, या

(हाय) केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग या विनाश या क्षति शामिल है, या

(iv) केंद्र सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध था,

और मामले के प्रभारी अभियोजक को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, वह तब तक अदालत में नहीं जाएगा, जब तक कि उसे केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति न दी जाए।

अभियोजन से हटने के लिए अपनी सहमति के लिए और न्यायालय, सहमति देने से पहले, अभियोजक को अभियोजन से हटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। ”

(8) राज्य के विद्वान वकील और निजी उत्तरदाताओं के वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद का जोरदार विरोध किया और कहा कि सरकारी वकील सरकार और जिले की सलाह के अनुसार अभियोजन से वापसी के लिए आवेदन दे सकता है। मजिस्ट्रेट और अपनी मर्जी से भी यदि वह संतुष्ट महसूस करता है कि अभियोजन से हटना सार्वजनिक हित, कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए है। यह सरकारी वकील की विशेष शक्ति है और अदालत ने वापसी के लिए सही सहमति दी है। यहां तक कि शासन व जिलाधिकारी ने भी मुकदमा वापस लेने का निर्देश दिया है।

(9) मैंने पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

(10) धारा 321 सी.आर.पी.सी. उन आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है जिन पर सरकारी अभियोजक आवेदन कर सकता है या उस पर विचार कर सकता है जिस पर अदालत को किसी मामले से हटने की सहमति देनी है। अभियोजन से हटने की शक्ति हमेशा एक अपवाद है, इसका प्रयोग न्याय प्रशासन के हित में किया जाना चाहिए। वापसी के कारणों को अदालत की न्यायिक चेतना को संतुष्ट करना चाहिए और केवल वैध आधार के बिना वापसी का निर्देश देने वाला सरकार का आदेश सरकारी अभियोजक द्वारा आवेदन दायर करने के लिए पर्याप्त नहीं है और अदालत द्वारा वापसी का आदेश पारित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

(11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, निर्णयों की श्रृंखला में, उन परिस्थितियों पर विचार किया है जिनके तहत लोक अभियोजक अभियोजन से पीछे हट सकता है। कुछ प्रासंगिक निर्णयों के अंश इस प्रकार हैं:-

(12) बलवंत सिंह बनाम बिहार राज्य (1), माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"वापसी पर निर्णय लेने की वैधानिक जिम्मेदारी पूरी तरह से लोक अभियोजक पर निहित है। यह गैर-समझौता योग्य बात है और इसे उन लोगों के पक्ष में नहीं बदला जा सकता जो प्रशासनिक स्तर पर उनसे ऊपर हों। आपराधिक प्रक्रिया संहिता एकमात्र मास्टर (एल) (1977)4 एससीसी448 है

लोक अभियोजक का और उसे केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में ही मार्गदर्शन करना होता है। इसलिए निर्देशित, इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अभियोजन वापस लेने या जारी रखने से सार्वजनिक न्याय का व्यापक उद्देश्य आगे बढ़ेगा या मंद होगा।"

अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य (2) में, शेओनंदनपेवा बनाम बिहार राज्य (3) में संविधान पीठ के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 321, आपराधिक संहिता के तहत मामले से वापसी के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं। प्रक्रिया:

“अदालत को यह देखना होगा कि क्या आवेदन अच्छे विश्वास, सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में किया गया है, न कि कानून की प्रक्रिया को विफल करने या दबाने के लिए। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत को यह देखना होगा कि क्या आवेदन ऐसी अनियमितताओं या अवैधताओं से ग्रस्त है जिससे सहमति दिए जाने पर स्पष्ट अन्याय हो सकता है। जब लोक अभियोजक अपने समक्ष मौजूद सभी सामग्री पर विचार करने के बाद वापसी के लिए आवेदन करता है, तो अदालत को ऐसी सामग्री पर विचार करके अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए और, ऐसे विचार पर, या तो सहमति देनी चाहिए या सहमति से इनकार करना चाहिए। इस धारा का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि अदालत को सहमति देते समय एक विस्तृत तर्कसंगत आदेश देना होगा। यदि, सहमति देने वाले आदेश

को पढ़ने पर, कोई उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी सहमति उपलब्ध सामग्री के समग्र विचार पर दी गई थी, तो सहमति देने वाले आदेश को आवश्यक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। धारा 321 न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षी तरीके से सहमति पर विचार करती है न कि न्यायिक तरीके से। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक अभियोजक द्वारा स्वतंत्र विचार के बाद और सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाते हुए, वापसी के लिए आवेदन ठीक से किया गया है। धारा 321 लोक अभियोजक को किसी भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने से हटने में सक्षम बनाती है। धारा 321 के तहत प्रयोग किया जाने वाला विवेक केवल अदालत के समक्ष सामग्री पर विचार करने की सहमति से ही सीमित है। अनुभाग को संतुष्ट करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि लोक अभियोजक ने अच्छे विश्वास में काम किया है और उसके द्वारा विवेक का प्रयोग उचित है।

(2) (2000) 8 एससीसी 710

(3) (1987) 1 एससीसी 288

राहुल अग्रवाल बनाम राकेश जैन और अन्य (4) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी: -

“10. इन निर्णयों के साथ-साथ इसी प्रश्न पर अन्य निर्णयों से, कानून बहुत स्पष्ट है कि अभियोजन को वापस लेने की अनुमति केवल न्याय के हित में ही दी जा सकती है। भले ही सरकार लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने का निर्देश देती है और इस आशय का एक आवेदन दायर किया जाता है, अदालत को सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या अभियोजन वापस लेने से न्याय की दिशा में प्रगति होगी। यदि मामले का अंत बरी होने की संभावना है और मामले के जारी रहने से केवल आरोपी को गंभीर उत्पीड़न हो रहा है, तो अदालत अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे सकती है। यदि अभियोजन वापस लेने से विवाद खत्म होने और पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित होने की संभावना है और यह न्याय के सर्वोत्तम हित में होगा, तो अदालत अभियोजन वापस लेने

की अनुमति दे सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत विवेक का प्रयोग अदालत द्वारा सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो कि पीड़ित पक्षों या राज्य के अनुरोध पर किया जा रहा है। उनकी शिकायत का निवारण करना। प्रत्येक अपराध समाज के प्रति अपराध है और यदि आरोपी ने अपराध किया है, तो समाज मांग करता है कि उसे दंडित किया जाना चाहिए। अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को दंडित करना समाज में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए, अभियोजन वापस लेने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब इसके लिए वैध कारण सामने आएंगे।"

(12) आपराधिक मामले से वापसी के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, आपराधिक मामलों से वापसी के लिए सरकारी अभियोजक का कार्य एक सार्वजनिक उद्देश्य से संबंधित है। लोक अभियोजक अदालत का एक अधिकारी होता है और उसका कर्तव्य सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करना है। ऐसा करने के लिए उन्हें जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है वह केवल न्याय प्रशासन के हित में है। निष्पक्षता, दक्षता और जवाबदेही अभियोजन प्रणाली की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। इन उद्देश्यों को सरकारी अभियोजक द्वारा शक्ति के स्वतंत्र प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी वकील को आपराधिक मामलों में अन्य अनुचित प्रभावों से मुक्त होकर आगे बढ़ना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, न तो आवेदन में, न ही तर्कों में, ऐसे कारणों और परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, न ही इस अदालत के ध्यान में लाया गया है जो वापसी का वारंट दे सकता है, यह संकेत दे सकता है कि दोनों के बीच शांति और सद्भाव कैसे बनाए रखा जाएगा। दलों

(4) एआईआर 2005 एससी 910

जब कोई समझौता न हो. शिकायत से एकतरफा मुकरना अर्थहीन है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस अदालत के दिनांक 17.08.2010 के आदेश पर विचार नहीं किया है, जिसके तहत दिनांक

15.07.2010 के आदेश में सुधार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि "... यह आदेश दिया गया है कि यह पंक्ति" कि मामले का अब समझौता हो गया है। 15 जुलाई 2010 के आदेश से हटाने का आदेश दिया गया।" अभियोजन से हटने पर व्यापक जनहित कैसे पूरा होगा? टायर आक्षेपित आदेश में उल्लिखित आधार जिनके आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा सहमति दी गई है, किसी भी ठोस कारण से समर्थित नहीं हैं। विवादित आदेश केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है। ट्रायल कोर्ट का आक्षेपित आदेश उन ठोस कारणों और परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट रूप से मौन है, जिन पर वापसी की अनुमति दी गई है। अभियोजन मामले से हटने के कारणों और परिस्थितियों को अदालत की न्यायिक अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए, जिनका आक्षेपित आदेश में अभाव है। ऐसे में आक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

(13) वर्तमान मामले में, जैसा कि आवेदन में उल्लिखित है, अभियोजन से हटने का एक और आधार यह है कि अभियोजन मामले की सफलता की कोई संभावना नहीं है। मेरी राय में, यह विशेष रूप से वापसी का आधार नहीं हो सकता है जब अभियोजन पक्ष के गवाह यानी याचिकाकर्ता और राजचंद्र घायल गवाह हों। सरकारी वकील की यह धारणा कि मामला सफल नहीं होगा, इस स्तर पर निराधार है जब अभियोजन पक्ष के एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सहमति देने से पहले, यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि न्याय के हित के अलावा किसी बाहरी आधार पर वापसी की मांग नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन मामले से हटने की सहमति देने से पहले इन पहलुओं पर विचार नहीं किया है। अदालत को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य के खिलाफ अपराध का फैसला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि सरकार ने अभियोजन से हटने का निर्देश दिया है, सहमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी वकील द्वारा वापसी के लिए दिया गया

आवेदन वर्तमान मामले में जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों और सबूतों की स्वतंत्र सराहना पर आधारित नहीं है।

(14) तत्काल याचिका में, सरकारी वकील द्वारा दायर आपराधिक मामले से वापसी के लिए आवेदन सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के पत्र जैसे बाहरी प्रभाव से मुक्त प्रतीत नहीं होता है। ब्लैकस्टोन लिखते हैं, न्याय राजा से उसके मुफ्त उपहार के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि वह जनता का प्रबंधक होता है कि जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे दे दे।"

सरकारी वकील द्वारा अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने कार्यालय के उच्चतम नैतिक और पेशेवर मानक को ध्यान में रखते हुए मामले का आवेदन दायर नहीं किया गया है। सरकारी वकील का अदालत, जनता, पीड़ितों, अभियुक्तों और गवाहों के प्रति अलग-अलग स्तर का दायित्व होता है।

(15) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पीटीसी) द्वारा आक्षेपित आदेश में दिए गए कारणों में भी कई पहलुओं की कमी है, जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में देखा गया है, जब मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में था और सहमति देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं थे। आपराधिक मामले से हटने के लिए, और इस तरह अभियोजन पक्ष को अभियोजन से हटने के लिए सहमति नहीं दी जानी चाहिए थी। मुकदमा न चलाने का एक ग़लत निर्णय, आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है।

(16) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विवादित आदेश दिनांक 25.8.2010 को रद्द कर दिया गया है, मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पीटीसी), कमल को भेज दिया गया है जो मामले को उसके मूल नंबर पर बहाल करेंगे और कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। इसे गुण-दोष के आधार पर जल्द से जल्द निपटाएं क्योंकि यह मामला 2005 से ही लंबित है।

(17) तद्नुसार, याचिका स्वीकार की जाती है।

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

(Trainee Judicial

Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा